एक नजर में

मेघवाल समाज का प्रदर्शन, मधुमक्खी हमले में मृत महिला के परिवार को 1 करोड़ मुआवजे की मांग

नीमच। जिले के रामपुरा में 20 बच्चों की जान बचाने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कंचन देवी मेघवाल की मौत के बाद अब गुस्सा बढ़ गया है। शुक्रवार को मेघवाल समाज के लोग बड़ी संख्या में कलेक्टर ऑफिस पहुंचे और प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। प्रदर्शन कर रहे लोग इस बात पर भड़क गए कि कलेक्टर खुद उनसे मिलने नहीं आए। जब अपर कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर ज्ञापन लेने पहुंचे, तो समाज के लोगों ने उन्हें लौटा दिया। उनका कहना था कि जब बड़े नेता इस मामले पर दुख जता चुके हैं, तो जिले के बड़े अफसर उनकी बात सुनने क्यों नहीं आ रहे। करीब एक घंटे तक कलेक्ट्रेट में नारेबाजी चलती रही। परिवार के लिए मदद की मांग– समाज ने मांग रखी है कि कंचन बाई के परिवार को एक करोड़ रुपए की मदद, वीरता सम्मान और सरकारी नौकरी दी जाए। साथ ही महिला बाल विकास अधिकारी को हटाने की बात भी कही गई है। लोगों का कहना है कि कंचन बाई के पति को लकवा मार गया है और बच्चों के सिर से मां का साया उठ गया है, ऐसे में परिवार के पास गुजारे का कोई रास्ता नहीं बचा है। क्या था मामला 2 फरवरी को आंगनवाड़ी केंद्र पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया था। बच्चों को बचाते समय कंचन बाई बुरी तरह घायल हो गई थीं, जिसके बाद उनकी जान चली गई। इसी बलिदान को लेकर अब समाज इंसाफ की गुहार लगा रहा है। बच्चों को बचाते-बचाते शहीद हुई कंचनबाई, 50 लाख मुआवजा और शासकीय नौकरी दो, नहीं तो प्रदेशव्यापी आंदोलन—सीटू का अल्टीमेटम नीमच। कर्तव्य, साहस और बलिदान की मिसाल बनी मध्यान्ह भोजन कार्यकर्ता कंचनबाई मेघवाल की मौत पर प्रशासनिक रवैये को लेकर अब आक्रोश फूट पड़ा है। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स (सीटू) ने इसे सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं की परीक्षा बताते हुए प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सीटू के प्रदेश अध्यक्ष पुषण भट्टाचार्य, महासचिव प्रमोद प्रधान, सचिव शैलेंद्र सिंह ठाकुर एवं मध्यान्ह भोजन समूह के संयोजक मनोहर बैरागी ने एक स्वर में कहा कि यह कोई सामान्य मृत्यु नहीं, बल्कि बच्चों की जान बचाने में दिया गया सर्वोच्च बलिदान है। प्रशासन को संवेदनहीन बयानबाजी छोड़कर तुरंत पीड़ित परिवार के पक्ष में ठोस निर्णय लेना चाहिए। प्रत्यक्षदर्शी बच्चों की गवाही: कंचनबाई ने बचाई जान प्रेसनोट में नेताओं ने बताया कि घटना के प्रत्यक्षदर्शी बच्चे और उनके अभिभावक साफ तौर पर कह चुके हैं कि कंचनबाई ने अपनी जान की परवाह किए बिना बच्चों को बचाया। यही नहीं, कंचनबाई के पति लकवाग्रस्त हैं, परिवार की स्थिति बेहद दयनीय है ऐसे में प्रशासन का किंतु-परंतु करना अमानवीय है। सीटू की दो टूक मांग सीटू ने स्पष्ट शब्दों में मांग रखी है कि कंचनबाई के परिवार को 50 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए और उनके पुत्र को तत्काल शासकीय नौकरी प्रदान की जाए। आंदोलन की चेतावनी– मध्यान्ह भोजन समूह की प्रदेश अध्यक्ष माया बैरागी, जिला अध्यक्ष माया पाटीदार, आशा यूनियन की जिला अध्यक्ष कृष्णा कांटे एवं आंगनबाड़ी यूनियन संयोजक सुनील शर्मा ने चेतावनी दी कि यदि स्थानीय प्रशासन ने शीघ्र निर्णय नहीं लिया तो मध्यान्ह भोजन कर्मी, स्वयं सहायता समूह और सीटू पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करेंगे।

सूने मकान से चोरी, इलाके में सनसनी

नीमच। केंट थाना क्षेत्र के बगीचा नंबर 13 इलाके में बीती रात चोरी की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। अज्ञात चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए देर रात बड़ी चोरी को अंजाम दिया, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मकान मालिक किशोर पंजाबी पिता कर्नल सिंह पिछले तीन दिनों से पारिवारिक कार्य से पंजाब गए हुए थे। मकान सूना होने की भनक लगते ही चोरों ने रात करीब 3 से 5 बजे के बीच मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया। इसके बाद अलमारी के ताले तोड़कर घर में रखा सामान खंगाल दिया। कमरे में पर्स सहित अन्य सामान बिखरा मिला, जिससे चोरी की पुष्टि हुई है। सुबह करीब 5 बजे मोहल्ले के निवासी अनिल कुमावत की नजर टूटे हुए ताले पर पड़ी। उन्होंने तुरंत शोर मचाया, जिस पर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही केंट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू की। पुलिस द्वारा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि चोरों की पहचान की जा सके। फिलहाल चोरी में कितनी नगदी और कितना कीमती सामान ले जाया गया है, इसका सही आंकलन मकान मालिक के नीमच लौटने के बाद ही हो सकेगा। घनी आबादी वाले क्षेत्र में हुई इस चोरी की वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय रहवासियों ने पुलिस प्रशासन से रात्रि गश्त बढ़ाने और संदिग्ध गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखने की मांग की है।

संकल्प से संमाधान शिविर में किसान सोहनलाल को मिला ट्रेक्टर

नीमच। जिले के जावद विकासखण्ड के ग्राम झांतला में शुक्रवार कोक संकल्प से समाधान शिविर में कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा द्वारा उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय बागवानी यंत्रीकरण योजना के तहत लांभावित किसान सोहन लाल पिता पन्नालाल धाकड़ को ट्रेक्टर की चाबी प्रदान कर ट्रेक्टर प्रदान किया गया है। इस मौके पर जिला पंचायत सीईओ श्री अमन वैश्णव, एसडीएम सुश्री प्रीती संघवी, उपसंचालक उद्यानिकी अतरसिह कन्नौजी व अन्य अधिकारी एवं ग्रामीणजन उपस्थित थे। कलेक्टर ने किसान सोहनलाल से चर्चा कर योजना तहत मिले 4.20 लाख के लाभ व 1.80 लाख के अनुदान के बारे में जानकारी ली व ट्रेक्टर का बागवानी कार्यो में उपयोग के बारे में भी चर्चा की।

जिला पंचायत अध्यक्ष के बेटे-भांजे से मारपीट, दोनों गंभीर

- सगराना फैक्ट्री विवाद में सरपंच के देवर समेत 30 लोगों ने पत्थर-डंडे मारे

नीमच। नीमच के सगराना गांव स्थित गोल्ड क्रैश फैक्ट्री में जिला पंचायत अध्यक्ष सज्जन सिंह चौहान के बेटे और भांजे पर जानलेवा हमला कर दिया गया। हमलावरों ने उनके साथ मारपीट कर वाहन को भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार दोपहर को जिला पंचायत अध्यक्ष सज्जन सिंह चौहान के बेटे इंद्रजीत सिंह और उनके भांजे आदित्य फैक्ट्री में रेत के डंपर खाली करवाने और उसका पेमेंट लेने के लिए गए थे। इसी दौरान वहां मौजूद हमलावरों ने उन पर अचानक पत्थर और लाठियों से हमला कर दिया। घटना में आदित्य के सिर और इंद्रजीत के हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। पुरानी रंजिश और रंगदारी का मामला- जिला पंचायत अध्यक्ष सज्जन सिंह चौहान ने आरोप लगाया है कि सगराना सरपंच रानीदेवी देवर महेंद्र सिंह ने अपने 30-35 साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। उन्होंने बताया कि आरोपी महेंद्र सिंह और उसके गुट का पहले से ही आपराधिक रिकॉर्ड रहा है।

इससे पहले भी इस समूह पर फैक्ट्री में अवैध वसूली (रंगदारी) मांगने के आरोप लगे थे, जिसके बाद पुलिस ने फैक्ट्री प्रबंधन की शिकायत पर उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया था।

आरोपियों ने जिला पंचायत अध्यक्ष की कार को क्षतिग्रस्त कर दिया।

घायलों का अस्पताल में इलाज जारी- वारदात की खबर मिलते ही कैंट थाना प्रभारी नीलेश अवस्थी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तुरंत दोनों लहूलुहान युवाओं को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है।

अस्पताल परिसर में भी सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल तैनात किया गया है। पीड़ितों के बयान के आधार पर पुलिस अब आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश

पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए हमलावरों की धरपकड़ शुरू कर दी है। कैंट पुलिस की अलग-अलग टीमें महेंद्र सिंह और उसके साथियों के संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं।

थाना प्रभारी नीलेश अवस्थी ने बताया कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल फैक्ट्री और आसपास के ग्रामीण इलाकों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है।

समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए किसानों के पंजीयन आज से प्रारंभ

- गेहूं उपार्जन के लिए 38 किसान पंजीयन केंद्र स्थापित

नीमच। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के मार्गदर्शन में नीमच जिले में गत वर्षानुसार इस वर्ष भी गेहूं उपार्जन के लिए किसान पंजीयन हेतु कुल 38 पंजीयन केंद्र स्थापित किए गए है। रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर गेहूं का उपार्जन ई-उपार्जन परियोजना तहत आज 7 फरवरी से प्रारम्भ होकर 7 मार्च 2026 तक किसान अपना पंजीयन नजदीकी पंजीयन केन्द्र पर निःशुल्क करवा सकते हैं। इस वर्ष सभी किसानों को नवीन पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पूर्व में कराये गये किसान पंजीयन मान्य नहीं होगें।

खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार गेहूं उपार्जन के लिए नवीन पंजीयन कराते समय कृषक निर्धारित आवेदन पत्र के साथ बैंक खाता, आधार नम्बर एवं ऋणपुस्तिका की छायाप्रति संलग्न करेगा। यदि कृषक द्वारा भूमि शिकमी पर ली गई है, तो शिकमी अनुबंध-पत्र की प्रति भी प्रस्तुत करना होगा।

यदि कोई किसान पंजीयन स्वयं भी करना चाहता है, तो वह स्वयं के मोबाईल अथवा कम्प्यूटर से पंजीयन हेतु निर्धारित लिंक पर जाकर, ग्राम पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर, जनपद पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर, तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधां केन्द्र पर, पूर्व वर्षों की भांति सहकारी समिति, स.।ल / स्त्रक्ष्ह/स्त्रक्ष्ह द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्र पर पंजीयन कर सकते है। पंजीयन की सशुल्क व्यवस्था (शुल्क राशि रूपयें 50/-), एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क पर, कॉमन सर्विस सेन्टर कियोस्क पर, लोकसेवा केन्द्र पर, निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर 50 रूपये शुल्क जमा कर पंजीयन करवाया जा सकता हैं। पंजीकृत किसान भाईयों से आग्रह किया गया है,

जिले के दूरस्थ गांव झांतला में संकल्प से समाधान शिविर में

- ग्रामीणों की समस्याओं से रूबरू हुए कलेक्टर
- अधिकारियों को ग्रामीणों की समस्याओं के त्वरित निराकरण को दिए निर्देश

नीमच। जिले की जावद विकासखंड के ग्राम झांतला मे शुक्रवार को संकल्प से समाधान अभियान के तहत क्लस्टर स्तरीय शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में कलेक्टर हिमांशु चंद्रा, ग्रामीणों की समस्याओं से रूबरू हुए और उनकी समस्या का त्वरित निराकरण करने के निर्देश संबंधित विभागों के जिला अधिकारियों को दिए हैं।

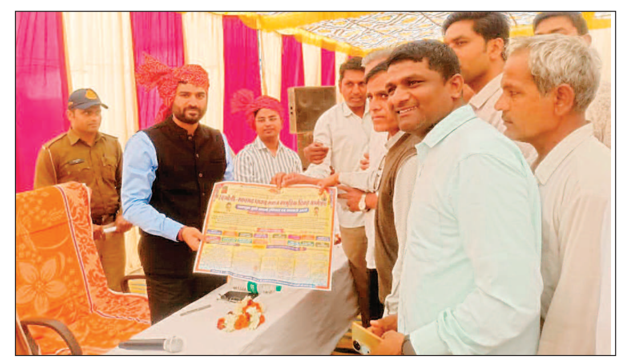

इस शिविर में झांतला के श्री राजेश वर्मा ने गांव के बड़े नाले की सफाई करवाने, गांव से सिंगोली रोड तक की सड़क का चौडीकरण एवं दुरूस्त करवाने, नया पुराना जलाशय की मरम्मत एवं सुधार नहरों की मरम्मत एवं सुधार करवाने की मांग की। इस पर कलेक्टर ने पंचायत सचिव को तत्काल जेसीबी लगवा कर, मुख्य नाले की सफाई करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को नया पुराना तालाब के सुधार एवं मरम्मत तथा नहरों का आवश्यक सुधार और तालाब का सुव्यवस्थित रख रखाव करवाने के निर्देश दिए।

जिले की सभी लाड़ली लक्ष्मियों को लंबित छात्रवृत्ति का भुगतान सुनिश्चित करें

शिविर में कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा को तीन लाड़ली लक्ष्मी छात्राओं द्वारा छात्रवृत्ति का भुगतान शेष होने की समस्या बताई। इस पर कलेक्टर ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिए, कि वे जिले की सभी लाड़ली लक्ष्मियों को छात्रवृत्ति वितरण की समीक्षा कर ले और भुगतान से शेष रही छात्रवृत्ति का भुगतान अविलंब सुनिश्चित करें।

ग्रामीणों की मांग पर कलेक्टर ने जल निगम की पाईपलाईन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों का गुणवत्तापूर्ण सुधार कार्य करवाने और घर के अंदर तक नीला पाइप पहुंचाकर, जल आपूर्ति करवाने के निर्देश जल निगम महाप्रबंधक को दिए हैं।

कृषि के साथ ही पशुपालन कर अपनी आय बढ़ाए - कलेक्टर

इस अवसर पर ग्रामीणों और किसानों से रूबरू होते हुए कलेक्टर ने कहा, कि मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव के निर्देशानुसार जिले में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए विशेष केसीसी अभियान चलाया जा रहा हैं। इस अभियान के तहत सभी पशुपालकों के केसीसी जारी करवाए जा रहे हैं। सभी पशुपालक पशुपालन केसीसी के लिए आवेदन करें और केसीसी के माध्यम से ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त कर उन्नत पशुपालन को बढ़ावा दे, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में सहयोग करें।

सभी सरपंच, सचिव गांव में अपशिष्ट प्रबंधन की समुचित व्यवस्था करें

विधायक परिहार ने भाटखेड़ा में किया कम्युनिटी हॉल का भूमि पूजन

नीमच। विधायक दिलीपसिंह परिहार ने ग्राम भाटखेडा में 15 लाख रूपए की लागत से उपयोगी डोम का भूमिपूजन किया। यह डोम सामाजिक-पारिवारिक कार्यक्रमों की सुविधाओं को बढाने के साथ आर्थिक बचत में भी सहायक सिद्ध होगा।

विधायक परिहार ने कहा कि सामुदायिक भवन का सदुपयोग अच्छे काम के लिए करते हुए सामूहिक रूप से बैठकर गांव में आपसी भाईचारे एवं सौहार्द्रपूर्ण वातावरण को बनाए रखना और ग्राम की समस्याओं का समाधान करना, विकास के लिए नई योजनाएं तैयार करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। गांव गांव में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य भाजपा सरकार ने किया है। किसान भाई खेती के साथ साथ फलदार वृक्ष भी लगाएं। गौपालन, भैंसपालन भी करें। देश में कृशि लाभ का धंधा बने, किसानों की आय दोगुना हो इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूर्व मुख्यमंत्री एवं कृशि मंत्री शिवराजसिंह चौहान लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार गांव गांव में विकास कार्यों की गंगा बहा रही है।

इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीमती वंदना खंडेलवाल, जनपद अध्यक्ष श्रीमती शारदा बाई मदनलाल धनगर, मंडल अध्यक्ष किशोरदास बैरागी, जिला मंत्री श्रीमती किरण शर्मा, महामंत्री वीरेन्द्रसिंह राठौड़, जगदीश परमार, सरपंच प्रतिनिधि कुलदीपसिंह राठौड़, वरिष्ठ नेता ईश्वरसिंह राठौड़, शुभम् शर्मा, जितेन्द्र अहीर एवं बड़ी संख्या में भाटखेड़ा के ग्रामवासी उपस्थित थे।

राज्य स्तरीय खेलो एमपी यूथ गेम्स जूडो प्रतियोगिता में नीमच के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन

नीमच। मध्य प्रदेश शासन एवं खेल युवा कल्याण विभाग द्वारा खेलों एमपी यूथ गेम्स अंतर्गत राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 27 से 30 जनवरी 2026 तक सागर (म.प्र.) में किया गया। नीमच जिला जूडो एसोसिएशन के सचिव एवं मुख्य प्रशिक्षक श्री भरत सिंह की कुमावत ने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश की 31 मान्यता प्राप्त जिला टीमों ने सहभागिता की प्रतियोगिता में नीमच जिला जूडो टीम ने भी सहभागिता की।

इस जुडो प्रतियोगिता में 31 जिला टीमो के बीच बालक/बालिका वर्ग के 16 वजन समुहो में कड़े मुकाबले हुए। बालिका वर्ग 48 कि.ग्रा वजन समुह में नीमच की वंशीका नागलोद पिता पिता श्री श्यामलाल ने अपने सभी मुकाबले जीतकर फाईनल में प्रवेश किया फाईनल मुकाबला नीमच की वंशींका नागलोद एंव भोपाल की आंचल के बीच हुआ इस कड़े मुकाबले में वंशींका नागलोद को थोड़े से अन्तर से पराजित होकर रजत पदक से ही सतुष्ट होना पड़ा।

इसके अतिरिक्त बालक वर्ग के विभिन्न वजन समुहो में नीमच के 50 कि.ग्रा वजन समुह मे हर्ष कुमावत पिता श्री राजेश कुमावत, 55 कि.ग्रा वजन समुह मे राकेश नागदा पिता श्री मोतीलाल, 60 कि.ग्रा वजन समुह मे अब्बास पिता इकबाल, 73 कि.ग्रा वजन समुह मे दक्ष मांगरिया श्री अतुल मांगरिया, 81 कि.ग्रा वजन समुह मे जलज बोरीवाल पिता श्री गोविन्द, 90 कि.ग्रा वजन समुह मे मंथन डाबले पिता श्री कमल एंव बालिका वर्ग में 40 कि.ग्रा वजन समुह मे काजल पिता श्री मनोज, 44 कि.ग्रा वजन समुह मे वंदना पाटीदार पिता श्री दिलिप, 52 कि.ग्रा वजन समुह मे रिया पाटीदार पिता श्री योगेन्द्र, 57 कि.ग्रा वजन समुह मे अलफिया मंसूरी पिता श्री वसीम, 63 कि.ग्रा वजन समुह मे भावना सौलंकी पिता श्री नारायण लाल, 70 कि.ग्रा वजन समुह मे रिद्धिमा सैनी पिता श्री मनोज इन सभी खिलाड़ियों ने क्वाटर फाईनल तक के अपने अपने मुकाबले जीते किन्तु मेडल फाईट में कड़े मुकाबले में थोड़े से अन्तर से पराजित मेडल जीतने से चुक गए।

एक नजर — शासन ने फैक्ट्री निर्माण के साथ जताई विकास और रोजगार की उम्मीद

मोरवन फैक्ट्री मामले में हाईकोर्ट ने स्टे वैकेट किया, ऑर्डर की कॉपी मिलने का इंतज़ार

नीमच। नीमच जिले के मोरवन गांव में प्रस्तावित सुविधि रेयॉन्स टेक्सटाइल फैक्ट्री को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद में बड़ा अपडेट सामने आया है। इस प्रकरण में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट द्वारा लगाया गया स्टे अब वैकेट कर दिया गया है। हालांकि न्यायालय का लिखित आदेश अभी आधिकारिक रूप से अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन प्रशासन को इसकी जानकारी मिल चुकी है और ऑर्डर की कॉपी कल मिलने की संभावना जताई जा रही है।

इस संबंध में एमपीआईडीसी के एडीएम राजेश राठौर ने बताया कि माननीय न्यायालय द्वारा स्टे वैकेट कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि न्यायालय के इस निर्देश के बाद फैक्ट्री निर्माण का रास्ता साफ हो गया है और आने वाले समय में इससे क्षेत्र के विकास के साथ-साथ ग्रामीणों के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

गौरतलब है कि 18 नवंबर को इस परियोजना को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फैक्ट्री निर्माण पर अंतरिम रोक लगाई थी। उस समय कोर्ट ने गोचर और चरनोई भूमि के व्यावसायिक उपयोग पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे। इसी आदेश के चलते फैक्ट्री निर्माण कार्य रुका हुआ था।

साथ ही ग्रामीणों ने फेक्ट्री निर्माण से पर्यावरणीय प्रभाव और मोरवन बांध की सुरक्षा को लेकर गंभीर आपत्तियां प्रशासन के समक्ष दर्ज कराते हुए लगातार आन्दोलन किया था। मोरवन बांध इस पूरे विवाद का केंद्र रहा है। यह बांध जावद नगरपालिका सहित आसपास के 30 से अधिक गांवों को पेयजल और सिंचाई की सुविधा देता है। ग्रामीणों और किसानों को आशंका थी कि टेक्सटाइल फैक्ट्री से निकलने वाला अपशिष्ट यदि बांध के जल में मिला तो इससे जल प्रदूषण के साथ खेती और जनस्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इन्हीं आशंकाओं के चलते गांव में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था, जो 6 नवंबर को हिंसक रूप भी ले चुका था। विरोध के दौरान ग्राम सभा ने प्रस्ताव पारित कर फैक्ट्री के लिए किए गए भूमि आवंटन को रद्द करने, सरकारी भूमि को गोचर घोषित करने और मोरवन बांध के पानी के औद्योगिक उपयोग पर रोक लगाने की मांग की थी।

क्षेत्रीय नेता पूरणमल अहीर और राजकुमार अहीर के नेतृत्व में यह आंदोलन लगातार तेज होता गया और अंततः गोचर की भूमि के आवंटन को लेकर मामला उच्च न्यायालय तक पहुंचा। जहां जानकारी मिली है की माननीय न्यायालय द्वारा सभी पक्षों को सुने जाने के बाद स्टे वेकेट यानी स्थगन आदेश रद्द कर दिया है।

पूरे मामले में अनावेदक पक्ष द्वारा अपना पक्ष माननीय न्यायालय के समक्ष रखा गया और×ठ्ठड्ढह्यश्च;अब स्टे वैकेट होने की जानकारी सामने आने के बाद ग्रामीणों में मिली-जुली प्रतिक्रिया देखी जा रही है। एक ओर प्रशासन और उद्योग पक्ष इसे क्षेत्रीय विकास और रोजगार के लिहाज से महत्वपूर्ण कदम बता रहा है, वहीं दूसरी ओर कई ग्रामीण अब भी पर्यावरण और जल सुरक्षा को लेकर आशंकित हैं। न्यायालय के लिखित आदेश की प्रतीक्षा के बीच गांव में ग्रामीणों का आगे क्या रुख होगा यह भविष्य के गर्भ में है।फिलहाल स्टे वैकेट होने से मोरवन टेक्सटाइल फैक्ट्री निर्माण का रास्ता खुलता दिखाई दे रहा है, लेकिन न्यायालय के आदेश की प्रति मिलने और उसके स्पष्ट निर्देश सामने आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि प्रशासन, कंपनी और ग्रामीणों के बीच इस मुद्दे पर किस तरह संतुलन बनता है।

माननीय न्यायालय द्वारा स्टे वैकेट कर दिया गया है।